

लखनऊ-कानपुर रैपिड रेल को एलडीए की अनुमति

जागरण संवाददाता, लखनऊ: कानपुर-लखनऊ के बीच रैपिड रेल चलाने की पहली बाधा पार हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) की योजना को सशर्त अनुमति दे दी है। एलडीए ने शासन से अनुरोध किया है कि प्रोजेक्ट का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाते समय लखनऊ की महायोजना का उल्लंघन न हो तो रैपिड रेल दौड़ा जा सकती है।

रैपिड रेल का प्रस्ताव 2015 में बना था। 2021 अप्रैल में तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बैठक में रिक्वेस्ट फार प्रोजेक्ट (आरएफपी) बनाने की बात कही थी, 2022 में शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी। योजना के अनुसार अमौसी एयरपोर्ट के पास

● लखनऊ महायोजना का उल्लंघन न करके एनसीआरटीसी चला सकता है रैपिड रेल



फाइल चित्र

लखनऊ-कानपुर के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाने के लिए डीपीआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित सभी विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद मुख्य डीपीआर बनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

पुनीत वत्स, सीपीआरओ, एनसीआरटीसी

मेरठ की जैसी मिलेंगी सुविधाएं

एनसीआरटीसी मेरठ में भी प्रोजेक्ट चला रहा है। मेरठ रैपिड रेल में हाई स्पीड आटोमैटिक डोर, तेज ब्रेकिंग सिस्टम और स्मार्ट टिकटिंग जैसी सुविधाएं हैं। लखनऊ-कानपुर रूट पर भी वैसी ही सुविधाएं देने की तैयारी है।

रैपिड रेल की शुरुआत होगी और जो कानपुर गंगापुल तक जाएगी। अभी लखनऊ से कानपुर तक जाने में करीब दो घंटे से अधिक समय लगता है, लेकिन रैपिड रेल से यह सफर 40 से 50 मिनट में

पूरा हो जाएगा। रैपिड रेल पर कोहरे का कोई असर नहीं होगा। ट्रेन ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जो हर मौसम में चलेगी।

एलडीए के मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया, लखनऊ

और कानपुर के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट को एलडीए ने करीब 10 दिन पहले सशर्त एनओसी शासन को भेज दिया है। कहा जा रहा है कि एनसीआरटीसी के अफसरों ने एक पखवाड़े पहले लखनऊ का दौरा किया था, उसी दौरान सहमति बनी थी। कानपुर और उन्नाव विकास प्राधिकरण पहले ही अनुमति दे चुके हैं।

अमौसी से बनी तक सड़क के समानांतर, बनी से उन्नाव के जैतीपुर तक नया मार्ग और फिर कानपुर-लखनऊ रेल ट्रैक के समानांतर अजगैन, उन्नाव, मगरवारा होकर गंगा बैराज तक रैपिड रेल चलाई जाएगी। बनी से उन्नाव के जैतीपुर तक वेयर हाउस, जैतीपुर से अजगैन तक औद्योगिक कॉरिडोर बना सकेगा और उन्नाव से गंगा पुल तक आवासीय योजनाएं धरातल पर उतर सकेंगी।
